[2021] 8 एस.सी.आर. 1161

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

मनोज कुमार एवं अन्य

(2021 की दीवानी अपील संख्या 913 – 914)

31 अगस्त, 2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि – वेतनमान – समानता में – पूर्व मध्य रेलवे (क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय रेलें) में नियोजित निजी सचिव (ग्रेड-II) ("पी.एस.-II") ने केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ("सी.एस.एस.एस.")/ रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ("आर.बी.एस.एस.एस.")/ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ("सी.ए.टी.") में कार्यरत अपने समकक्षों के साथ वेतन में समानता का दावा किया – अभिनिर्धारित: जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, समानता का कोई निरंतर इतिहास नहीं है, अर्थात, कभी समानता दी गई और कभी नहीं – ऐसा नहीं है कि छठा केंद्रीय वेतन आयोग सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता के तर्क से अनभिज्ञ था, लेकिन उसी पर ध्यान देने के बावजूद सचिवालय और गैर-सचिवालय कार्यालयों के बीच कुछ अंतर करने का प्रयास किया गया था – फिर भी कुछ हद तक, सचिवालय संगठनों और गैर-सचिवालय संगठनों के संबंध में एक अलग सिफारिश की गई थी – एक बार जब ये सिफारिशें अलग से की जाती हैं, तो पूर्ण समानता का निर्देश देना गैर-सचिवालय संगठनों के संबंध में अलग सिफारिशों को निरर्थक (ओटिओस) बनाना होगा – इसके अलावा, न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि आयोग ने स्वयं सभी पहलुओं पर विचार किया है और उचित विचार के बाद राय दी है कि पूर्ण समानता नहीं दी जानी चाहिए।

अपीलों की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने :

अभिनिर्धारित किया: 1. *वी.एन. नारायणप्पा एवं अन्य* के मामले में सही परिप्रेक्ष्य लिया गया है, जहां तक 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कौन सा खंड लागू होगा। यह न्यायालय पाता है कि एक बार जब यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालयों को गैर-सचिवालय संगठनों के रूप में माना जाना है, तो ऐसे गैर-सचिवालय संगठनों से संबंधित 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रतिवेदन के कंडिका 3.1.14 में विशिष्ट सिफारिशें लागू होंगी। कंडिका 3.1.9 में की गई टिप्पणियों, जो सचिवालय कार्यालयों के संबंध में निजी सचिव/प्रशाखा अधिकारी के समकक्ष के बीच समानता देती हैं, उन्हें गैर-सचिवालय संगठनों पर भी *यथावश्यक (म्यूटैटिस म्यूटैंडिस) परिवर्तन* के साथ लागू नहीं माना जा सकता है। अगर हम अन्यथा राय देते हैं और सभी को बराबर मानते हैं, तो 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए अपने विवेक से गैर-सचिवालय संगठनों के लिए अलग सिफारिशें करने का कोई उद्देश्य नहीं रहा होता। ऐसा नहीं है कि आयोग सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता के तर्क से अनभिज्ञ था जैसा कि कंडिका 3.1.2 और 3.1.3 में निपटा गया था, लेकिन उसी पर ध्यान देने के बावजूद सचिवालय और गैर-सचिवालय कार्यालयों के बीच कुछ अंतर करने का प्रयास किया गया था। [कंडिका 14] [1173-ई-एच]

2. वेतन आयोग विसंगतियों को हल करने के उद्देश्य से स्थापित एक विशेषज्ञ निकाय है। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि विचाराधीन विसंगति को उत्तरदाताओं के समान स्थितियों के उम्मीदवारों के अनुरोध पर वेतन आयोग को भेजा गया था और इस प्रकार, छठा केंद्रीय वेतन आयोग समानता के दावे और उस संबंध में एक सिफारिश करने की आवश्यकता से अवगत था। अपने विवेक में बेहतर वेतनमान देते हुए भी इसने गैर-सचिवालय संगठनों के लिए एक अलग सिफारिश बनाए रखने का प्रयास किया है। [कंडिका 15][1174-ए-बी]

3. उत्तरदाताओं का एक अभिवचन यह भी है कि दोनों संवर्गों के लिए भर्ती प्रक्रिया समान थी और व्यक्तियों को एक से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता था। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वास्तव में, उत्तरदाताओं का तर्क है कि ऐसे समय भी रहे हैं जब एक साझा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और कभी-कभी परीक्षाएं अलग से आयोजित की जाती थीं। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अपर महान्यायाभिकर्ता द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संवर्ग अलग हैं और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियम भी अलग हैं। रेलवे बोर्ड के तहत आशुलिपिक आर.बी.एस.एस. नियम, 1971, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सी.एस.एस. नियम, 1969 और सी.एस.एस.एस. नियम, 2010 द्वारा नियंत्रित होते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आशुलिपिक सी.ए.टी.एस.एस. नियम, 2013 द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये वे पद हैं जिनके साथ उत्तरदाताओं ने समानता की मांग की। दूसरी ओर, क्षेत्रीय रेलवे में कार्यरत उत्तरदातागण भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 107 द्वारा नियंत्रित होते थे। रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे में आशुलिपिकों के पदोन्नति का मार्ग और चैनल, बताया गया है, पूरी तरह से अलग हैं। [कंडिका 16][1174-सी-एफ]

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि स्थानांतरण के कुछ मामले थे, लेकिन वे व्यक्ति थे जिन्हें कार्य की आवश्यकता के लिए रेलवे बोर्ड में लाया गया था – ऐसा नहीं था कि वे रेलवे बोर्ड में समाहित हो गए थे। ऐसे मामले भी थे जहां रेलवे बोर्ड से क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों में स्थानांतरण हुए, लेकिन वह ऐसे अधिकारियों के विशिष्ट अनुरोध पर था और मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया गया और उन्हें फिर वरिष्ठता सूची के निचले पायदान पर लेनी पड़ी। [कंडिका 17][1174-एफ-जी]

5. कंडिका 3.1.3, जिसमें सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता से निपटा गया था, ने क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन के अग्रणी किनारे पर होने के मद्देनजर, क्षेत्रीय कार्यालयों और सचिवालय में नियोजित समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच समानता के लिए एक मामले का समर्थन किया है। हालांकि, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि

सहायक के ग्रेड तक समानता को पूर्ण होना होगा। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि उससे परे *"पूरे बोर्ड में कार्यात्मक विचारों और सापेक्षताओं को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम और करियर प्रगति को अलग होना होगा क्योंकि पूर्ण समानता देना संभव या यहां तक कि न्यायोचित भी नहीं हो सकता है।"* यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, तो लाभ उत्तरदाताओं को प्राप्त नहीं हो सकता है और हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सहायक के स्तर तक समानता दिए जाने के परिणामस्वरूप (जो उन्हें ₹4200 (बाद में ₹4600) के ग्रेड में रखता है), उत्तरदाताओं को, एक पद उच्चतर होने के कारण, स्वचालित रूप से एक उच्चतर ग्रेड प्राप्त करना होगा। [कंडिका 18][1174-जी-एच; 1175-ए-बी]

19. हम वेतन आयोग की प्रतिवेदन के उपर्युक्त कंडिकाओं की व्याख्या करने में जिस दृष्टिकोण को अपनाना चाहते हैं, उसमें *भारत संघ बनाम तरित रंजन दास* के मामले में की गई टिप्पणियों से पुष्टि मिलती है, जहां यह राय दी गई थी कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को केवल पदनाम के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से निपटते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस आधार पर किसी भी समतुल्यता का कोई प्रश्न नहीं था। उक्त मामला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आशुलिपिकों से संबंधित था। यह देखते हुए कि एक सामान्य बयान के रूप में यह कहना सही था कि एक आशुलिपिक के काम की मूल प्रकृति बहुत हद तक समान रहती है चाहे वे सचिवालय में एक अधिकारी के लिए काम कर रहे हों या अधीनस्थ कार्यालय में एक अधिकारी के लिए; यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि आयोग ने स्वयं सभी पहलुओं पर विचार किया है और उचित विचार के बाद राय दी है कि पूर्ण समानता नहीं दी जानी चाहिए। [कंडिका19][1175-सी-ई]

20. अंत में हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता का पहलू सिफारिशें करते समय आयोग द्वारा स्वयं ध्यान में लिया गया

मामला था। फिर भी कुछ हद तक, सचिवालय संगठनों और गैर-सचिवालय संगठनों के संबंध में एक अलग सिफारिश की गई थी। एक बार जब ये सिफारिशें अलग से की जाती हैं, तो पूर्ण समानता का निर्देश देना गैर-सचिवालय संगठनों के संबंध में अलग सिफारिशों को निरर्थक बनाना होगा। यदि कोई कह सकता है, तो इन अलग सिफारिशों को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि सभी को हर पहलू पर समानता पर माना जाना था। [कंडिका20] [1175-ई-जी]

वी. एन. नारायणप्पा एवं अन्य बनाम सचिव, रेलवे बोर्ड आदि। **(कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 2014 की बैंगलोर में मूल आवेदन संख्या 640-649 और 1001-1030 पर दिनांक 13.04.2016 को निर्णय);** *एस. आर. धीर एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में वाद संख्या ओ.ए. संख्या 164/2009 पर दिनांक 19.02.2009 को निर्णय);** *रबींद्र नाथ बसु एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(कैंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, बैंगलोर पीठ में ओ.ए. संख्या 2102/2010 पर दिनांक 16.05.2011 को निर्णय);** *भारत संघ बनाम तारित रंजन दास* **(2003) 11 एस.सी.सी. 658 : [2003] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 339 – संदर्भित।**

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

[2003] 4 अनुपूरक एस.सी.आर. 339	**संदर्भित**	**कंडिका19**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 913-914/2021 ।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद [सी.डब्ल्यू.जे.सी.] संख्या 15717/2016 के दिनांक 21.03.2017 का निर्णय और आदेश तथा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15717/2016 में आर.ए. संख्या 191/2017 के दिनांक 23.08.2017 का आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए: आर.एस. सूरी, ए.एस.जी., सुश्री वी. मोहना, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्तागण, नलिन कोहली, पी.वी. योगेश्वरन, अमरीश कुमार, अधिवक्तागण।

उत्तरदातओं के लिए: विकास सिंह, शंकर राजू, वरिष्ठ अधिवक्तागण, विवेक सिंह, सुश्री दीपिका कालिया, कपिश सेठ, मृत्युंजय सिंह, सी.पी. राजवार, उदिता सिंह, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल न्यायमूर्ति

1. भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नागरिक नियोक्ता है जिसमें छह उत्पादन इकाइयां[1] और अठारह क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में तीन से छह मंडल हैं। 31.03.2005 तक कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 14 लाख बताई गई थी जिसमें कर्मचारी शक्ति का निम्न वितरण था:

समूह	स्थिति में
ए	8285
बी	7247
सी	873536
डी	521578
कुल	**1410646***

* भारतीय रेल वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे 2019-20 के अनुसार, 31.03.2020 तक वर्तमान संख्या लगभग 12,53,592 है।

1 भारतीय रेलवे वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे 2019-20 पृष्ठ 6.

2. छठे केंद्रीय वेतन आयोग (**"6 वां सीपीसी"**) की प्रतिवेदन का अध्याय 7.36 रेल मंत्रालय से संबंधित है और यह दर्शाता है कि इसमें रेलवे बोर्ड सहित चौदह विभाग हैं। प्रतिवेदन में इन विभिन्न विभागों की मांगों की जांच की गई, जो विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के लिए उच्च वेतनमान और भत्ते की मांग कर रहे थे। हम वर्तमान मामले में पूर्व मध्य रेलवे (क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय रेलवे) में नियोजित निजी सचिव (ग्रेड-II) **("पीएस-II")** द्वारा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा **("सीएसएसएस")**/ रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा **("आरबीएसएसएस")**/ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण **("सीएटी")** में कार्यरत अपने समकक्षों के साथ वेतन में समानता के दावों से संबंधित हैं। हम इस स्तर पर ही ध्यान दे सकते हैं कि ऐसी समानता के दावे पर आपसी विरोधी न्यायिक राय रही हैं, जिन पर हम बाद में आएंगे।

3. हम ध्यान दे सकते हैं कि 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग ने रेल मंत्रालय में कुछ संवर्गों से संबंधित सामान्य श्रेणी के पदों द्वारा की गई मांगों का कंडिका 7.36.95 में उल्लेख किया। सामान्य श्रेणी के पदों में से एक "टंकक और आशुलिपिक" का है। इसके बाद, कंडिका7.36.96 में, यह देखा गया कि इन सामान्य श्रेणियों को आयोग ने प्रतिवेदन में कहीं और शामिल किया है। यह कहा गया था कि उनमें की गई सिफारिशें रेल मंत्रालय में सामान्य श्रेणी के पदों के संबंध में भी लागू होंगी, इस श्रेणी के लिए कोई अलग सिफारिशें नहीं की गई हैं। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में हमें 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रतिवेदन के अध्याय 3.1 की ओर मुड़ना होगा, जो "भारत सरकार में मुख्यालय संगठनों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालय कर्मचारियों" से संबंधित है। सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता को खंड 3.1.2 और 3.1.3 में निर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

"सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता

3.1.2 सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक पद मुख्यतः केंद्रीय स्टाफ़िंग योजना के तहत प्रतिनियुक्ति पर अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय समूह 'ए' सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। मध्य स्तर के कुछ पद केंद्रीय सचिवालय सेवाओं, रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रक्षा मंत्रालय में रक्षा बल मुख्यालय सेवाओं और विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा ('बी') के अधिकारियों द्वारा भी अभिनिर्धारित किए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से, सचिवालय में विभिन्न सेवाओं को क्षेत्रीय कार्यालयों में समान पदों पर बढ़त दी गई है। यह इस आधार पर किया गया था कि सचिवालय में कार्यालय कर्मचारी जटिल कर्तव्यों का पालन करते हैं और नीतिगत निहितार्थों वाले मुद्दों का विश्लेषण करने में शामिल होते हैं, जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके समकक्ष कार्मिक और सामान्य प्रशासन से संबंधित नियमित मामलों से संबंधित नियमित कार्य करते हैं। सचिवालय में विभिन्न पदों के लिए बढ़त को न्यायोचित ठहराने के लिए एक और तर्क यह उपयोग किया जाता है कि सचिवालय में, स्तर कूद (लेवल जंपिंग) होती है और सहायक के ग्रेड आदि में कर्मचारी फाइलें सीधे अवर सचिव, उप सचिव आदि के निर्णय लेने के स्तरों पर जमा करते हैं।"

3.1.3 सचिवालय कार्यालयों में उच्च वेतनमान अतीत में न्यायोचित हो सकते थे जब उचित नीतियों का सूत्रीकरण सर्वोच्च महत्व का था। वर्तमान स्थिति अलग है। आज, किसी भी सरकारी नीति के संबंध में सबसे कमजोर कड़ी वितरण के चरण पर है। यह घटना भारत के लिए स्थानिक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वितरण लाइनों को मजबूत करने और विकेंद्रीकरण पर बढ़ता जोर है जिसमें वितरण बिंदुओं पर अधिक भूमिका सौंपी जाती है जो वास्तव में निर्धारित करता है कि सामान्य नागरिक सरकार की किसी भी नीतिगत पहल से क्या लाभ प्राप्त करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय प्रशासन के अग्रणी किनारे पर हैं और अधिकांश मामलों में, यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई विशेष नीति उपभोक्ता को वास्तविक लाभ के मामले में सफलता या विफलता में

बदलती है या नहीं। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों में और सचिवालय में नियोजित समान रूप से स्थित कर्मियों के बीच समानता देने का समय आ गया है। **यह समानता सहायक के ग्रेड तक पूर्ण होनी होगी। इससे परे, पूर्ण समानता देना संभव या यहां तक कि न्यायोचित भी नहीं हो सकता है क्योंकि कार्यात्मक विचारों और सापेक्षताओं को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम और करियर प्रगति को पूरे बोर्ड में अलग होना होगा।"**

(बल दिया गया)

4. कंडिका3.1.9 में सिफारिशें एल.डी.सी. से निदेशक तक विभिन्न पदों के लिए की गई हैं, जिसमें प्रशाखा अधिकारी शामिल हैं, इस चेतावनी के साथ कि ₹8000-13500 के वेतनमान वाले अनुभाग अधिकारियों के मामले में, यह स्केल केवल उन्हीं संगठनों/सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा जिनका सीएसएस/ सीएसएसएस के साथ एक ऐतिहासिक समानता रही है। हालांकि, हम ध्यान देते हैं कि विभिन्न पदों के संशोधित वेतनमानों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से पहले, कंडिका3.1.9 में यह देखा गया है कि: *"ये सिफारिशें इन सेवाओं में निजी सचिव/समकक्ष के पद पर भी यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगी।"*

5. हम ध्यान दे सकते हैं कि उत्तरदातओं का निवेदन है कि यह खंड ही शासन करना चाहिए; और यह निजी सचिवों/समकक्ष के पद और एक प्रशाखा अधिकारी के पद के बीच समानता की सिफारिश करता है। अब हम खंड 3.1.14 की ओर मुड़ते हैं जो गैर-सचिवालय संगठनों के लिए सिफारिशों से संबंधित है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, जिन पहलुओं को हमारे सामने उठाने की मांग की जाती है, वे इस कंडिका के तहत विशेष रूप से निपटाए जाते हैं; और इस प्रकार, उत्तरदाता का दावा कि उनका वेतनमान कंडिका 3.1.9 द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, गलत है। ये कंडिका निम्नानुसार हैं:

"सिफारिशें

3.1.9 तदनुसार, आयोग सभी सचिवालय सेवाओं (सी.एस.एस. के साथ-साथ गैर-भागीदार मंत्रालयों/विभागों/संगठनों सहित) में अनुभाग अधिकारियों के प्रवेश स्केल को ₹7500-12000 तक उन्नयन करने की सिफारिश करता है, जो ₹4800 के ग्रेड वेतन के साथ ₹8700-34800 के संशोधित वेतन बैंड पी.बी. 2 के संगत है। इसके अलावा, सी.एस.एस. में पहले से उपलब्ध व्यवस्था के समान, अन्य सचिवालय कार्यालयों में अनुभाग अधिकारियों, जिनकी सी.एस.एस./सी.एस.एस.एस. के साथ हमेशा से स्थापित समानता रही है, को निचले ग्रेड में चार वर्षों की सेवा पूरी होने पर ₹4800 के ग्रेड वेतन के साथ ₹8700-34800 के संशोधित वेतन बैंड पी.बी. 2 के संगत समूह 'बी' में ₹8000-13500 का स्केल विस्तारित किया जाएगा। यह सभी सचिवालय कार्यालयों के बीच पूर्ण समानता सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ₹4800 के ग्रेड वेतन वाला वेतन बैंड पी.बी. 2 ₹8700-34800 प्रशाखा अधिकारी के पद के लिए इन सेवाओं में केवल मौजूदा सापेक्षताओं को बनाए रखने के लिए अनुशंसित किया जा रहा है जो तब बाधित हो गई थी जब स्केल केवल सी.एस.एस. में अनुभाग अधिकारियों तक विस्तारित किया गया था। वेतन बैंड पी.बी.-2 में ₹4800 का ग्रेड वेतन रखने वाले ग्रेड को, अन्यथा, एक नियमित ग्रेड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और किसी भी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें इन सेवाओं में निजी सचिव/समकक्ष के पद पर भी यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगी। सचिवालय कार्यालयों में पदों की संरचना अब निम्नानुसार होगी:-

पद	पूर्व संशोधित वेतनमान	संगत संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
निम्न श्रेणी लिपिक	₹3050-4590	पीबी-1 का ₹4860-20200 के साथ ग्रेड वेतन ₹1900
उच्च श्रेणी लिपिक	₹4000-6000	पीबी-1 का ₹4860-20200 के साथ ग्रेड वेतन ₹2400
सहायक	₹6500-10500	पीबी-2 का ₹8700-34800 के साथ ग्रेड वेतन ₹4200
प्रशाखा अधिकारी	₹7500-12000 ₹8000-13500* (4 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर)	पीबी-2 का ₹8700-34800 के साथ ग्रेड वेतन ₹4800 पीबी-2 का ₹8700-34800 के साथ ग्रेड वेतन ₹5400* (4 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर)
अवर सचिव	₹10000-15200	पीबी-3 का ₹15600-39100 के साथ ग्रेड वेतन ₹6100
उप सचिव	₹12000-16500	पीबी-3 का ₹15600-39100 के साथ ग्रेड वेतन ₹6600
निदेशक	₹14300-18300	पीबी-3 का ₹15600-39100 के साथ ग्रेड वेतन ₹7600

*यह स्केल केवल उन्हीं संगठनों/सेवाओं में उपलब्ध होगा जिनकी सीएसएस/ सीएसएसएस के साथ एक ऐतिहासिक समानता रही है। एएफएचक्यूएसएस/ एएफएचक्यूएसएसएस/आरबीएसएस जैसी सेवाएं और मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में लिपिकीय/सचिवालय पद जैसे कि एमईए, संसदीय कार्य मंत्रालय, सीवीसी, यूपीएसई आदि इसलिए शामिल होंगे।"

"गैर-सचिवालय संगठनों के लिए सिफारिशें

3.1.14 पिछले कंडिकाओं में स्थापित सिद्धांत के अनुसार, क्षेत्रीय और सचिवालय कार्यालयों के बीच समानता की सिफारिश की जाती है। इसमें कुछ ग्रेडों का विलय शामिल होगा। आशुलिपिक संवर्ग में, मौजूदा स्केल ₹4500-7000/₹5000-8000 और ₹5500-9000 में आशुलिपिक ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के पद, इसलिए, विलय हो

जाएंगे और उन्हें उच्च वेतनमान ₹6500-10500 में रखा जाएगा। गैर-सचिवालय कार्यालयों में लिपिकीय पदों के मामले में, क्रमशः ₹5000-8000, ₹5500-9000 और ₹6500-10500 के वेतनमानों में मुख्य लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 3 के पद विलय हो जाएंगे। इसलिए, क्षेत्रीय संगठन में मौजूदा और संशोधित संरचना निम्नानुसार होगीः-

<table>
<tr><td rowspan="2">पदनाम</td><td rowspan="2">वर्तमान वेतनमान (₹)</td><td rowspan="2">अनुशंसित वेतनमान (₹)</td><td colspan="2">संगत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन</td></tr>
<tr><td>वेतन बैंड</td><td>ग्रेड वेतन</td></tr>
<tr><td>निम्न श्रेणी लिपिक</td><td>3050-4590</td><td>3050-4590</td><td>वेतन बैंड 1</td><td>₹1900</td></tr>
<tr><td>उच्च श्रेणी लिपिक</td><td>4000-6000</td><td>4000-6000</td><td>वेतन बैंड 1</td><td>₹2400</td></tr>
<tr><td>मुख्य लिपिक / सहायक / आशुलिपिक ग्रेड 2 / समकक्ष</td><td>4500-7000 / 5000-8000</td><td rowspan="3">6500-10500</td><td rowspan="3">वेतन बैंड 2</td><td rowspan="3">₹4200</td></tr>
<tr><td>कार्यालय अधीक्षक / आशुलिपिक ग्रेड 1 / समकक्ष</td><td>5500-9000</td></tr>
<tr><td>अधीक्षक / सहायक प्रशासनिक अधिकारी / निजी सचिव / समकक्ष</td><td>6500-10500</td></tr>
<tr><td>प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 2 / वरिष्ठ निजी सचिव / समकक्ष</td><td>7500-12000</td><td>7500-12000 (नए रंगरूटों के लिए प्रवेश ग्रेड) 8000-13500 (4 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर)</td><td>वेतन बैंड 2</td><td>₹4800 (4 वर्षों के बाद ₹5400)</td></tr>
<tr><td>प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 1</td><td>1000-15200</td><td>10000-15200</td><td>वेतन बैंड 2</td><td>₹6100</td></tr>
</table>

कंडिका 3.1.14 का एक अवलोकन यह दिखाएगा कि आशुलिपिक (ग्रेड-2) का विशेष रूप से इस कंडिका के तहत उल्लेख किया गया है और यह क्षेत्रीय और सचिवालय कार्यालयों के बीच समानता के पहलू से संबंधित है।

6. हम ऊपर बताए गए मुद्दे को सुलझाना सही समझते हैं, जो 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को सीधे तौर पर पढ़ने पर अभिनिर्धारित है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे तर्क और समता के दावे इसी बात पर अभिनिर्धारित होंगे कि कौन सा खंड लागू होगा।

7. हमारे विचार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि, हालांकि एक टिप्पणी है कि सिफारिशें कंडिका 3.1.9 के तहत सेवा में निजी सचिवों और उसके समकक्ष पदों पर यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगी; बाद के कंडिका 3.1.14 ने विशेष रूप से क्षेत्रीय और सचिवालय कार्यालयों के बीच समानता के पहलू से निपटा है, जो वास्तव में हमारे सामने दावे का विषय है।

8. उत्तरदाताओं का निवेदन है कि 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कंडिका 3.1.9 कंडिका 7.36.95 और 7.36.96 के अनुसरण में जारी किया गया है। रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिकों के लिए कोई अलग सिफारिशें नहीं की गई हैं। कंडिका3.1.9, जो विशेष रूप से अनुभाग अधिकारियों से संबंधित है, यह भी प्रदान करता है कि यह इन सेवाओं में निजी सचिवों पर यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू होता है। इस निवेदन का आधार इसलिए यह है कि कंडिका3.1.14 रेलवे के अलावा अन्य गैर-सचिवालय संगठनों के लिए सिफारिशों से संबंधित है, और उन्हें सचिवालय संगठनों के रूप में माना जाना चाहिए। हमारे विचार में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। विभिन्न केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के आपसी विरोधी विचारों के राय में, अधिकरण, बैंगलोर के 2014 के मूल आवेदन संख्या 640-649 और 1001-1030 में दिया गया विचार अपीलकर्ताओं के मामले के पक्ष में जाने की मांग करता है।

9. यदि हम उस निर्णय (***वी. एन. नारायणप्पा और अन्य बनाम सचिव, रेलवे बोर्ड आदि I***) की ओर मुड़ते हैं, जो 13.04.2016 को निपटाया गया था, तो तथ्यों का संपूर्ण समूह दक्षिणी रेलवे में समान रूप से स्थित निजी सचिवों (ग्रेड 2) के मामले से संबंधित है।

इस निवेदन पर विचार करते हुए, अधिकरण ने अधिकरण की मद्रास पीठ द्वारा 05.06.2012 को निपटाए गए ओ.ए. संख्या 658/2010 में एक अलग राय पर ध्यान दिया, जिस पर आवेदकों ने अवलंबन करने की मांग की थी। वह निर्णय बदले में अधिकरण की दिल्ली में प्रधान पीठ के ओ.ए. संख्या 164/2009 के मामले में 19.02.2009 को निपटाए गए एक पहले के विचार पर अभिनिर्धारित था (***एस. आर. धीर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य***), जो अधिकरण के निजी सचिवों (ग्रेड-2) के संबंध में था। इस समय, यह नोट करना महत्वपूर्ण हो सकता है कि यहां उत्तरदाताओं ने भी अधिकरण पटना के सामने अपने ओ.ए. में, अधिकरण मद्रास के उपर्युक्त निर्णय के साथ समानता का दावा किया। अधिकरण की मद्रास पीठ ने ध्यान दिया था कि सरकार द्वारा अभिलेख पर कोई भर्ती नियम नहीं रखे गए थे जबकि यह कहा गया था कि शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं आदि के अलग मानक मौजूद हैं। इस प्रकार, अधिकरण की मद्रास पीठ का विचार सामग्री की अनुपस्थिति पर और दिल्ली में प्रधान पीठ के साथ समानता के कारण पर अभिनिर्धारित था, भले ही दिल्ली में प्रधान पीठ ने अधिकरण आशुलिपिकों (ग्रेड 2) के अधिकारियों के मामले से निपटा था और ऐतिहासिक समानता के आधार पर ओ.ए. को अनुमति दी थी।

10. हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा मद्रास अधिकरण के विचारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। निर्णय को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका और एक पुनर्विचार याचिका दोनों को संक्षेप में खारिज कर दिया गया था और परिणामस्वरूप, इस मामले में निर्णय किए जाने वाले प्रश्न को इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से नहीं निपटाया गया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मामलों में विभिन्न आदेशों का कार्यान्वयन हुआ है, जो वास्तव में प्रकृति में विरोधाभासी हैं।

11. अधिकरण की बैंगलोर पीठ ने गुण-दोष के आधार पर मुद्दे को निर्धारित करने की मांग करते हुए प्रधान पीठ (दिल्ली) के ओ.ए. संख्या 2102/2010 में ***रबींद्र नाथ बसु और***

अन्य बनाम भारत संघ और अन्य और अन्य संबंधित मामलों में 16.05.2011 को निपटाए गए एक पहले के निर्णय से शक्ति की मांग की, जो आयुध कारखाना बोर्ड के सहायक कर्मचारी अधिकारियों के मामले से संबंधित था। अधिकरण ने उसमें राय दी कि आवेदक एक गैर-सचिवालय संगठन से संबंधित थे और इसलिए 6 वें वेतन आयोग के कंडिका3.1.14 में निर्धारित वेतनमान द्वारा शामिल होंगे।

12. यदि हम ***वी. एन. नारायणप्पा और अन्य***[2] में चर्चा पर ध्यान दें, तो ऐतिहासिक समानता उन पहलुओं में से एक है जिसकी जांच की गई है। वर्तमान मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि 1 और 2 वें वेतन आयोगों की सिफारिशों के तहत ऐसी ऐतिहासिक समानता थी। हालांकि, 3 और 4 वें वेतन आयोगों ने समानता नहीं दी और 5 वें वेतन आयोग ने सीमित हद तक समानता दी। इस प्रकार, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, समानता का कोई निरंतर इतिहास नहीं है, यानी, कभी समानता दी गई और कभी नहीं। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त नोट से उपलब्ध इतिहास निम्नानुसार है:

केंद्रीय वेतन आयोग	आरबीएसएस**(₹)**	क्षेत्रीय रेलवे/क्षेत्रीय अधिकारी **(₹)**
1 वें वेतन आयोग	160-450/-	160-450/-
2 वें वेतन आयोग	210-530/-	210-530/-
3 वें वेतन आयोग	650-1200/-	650-960/-
4 वें वेतन आयोग	2000-3500/-	2000-3200/-
5 वें वेतन आयोग	6500-10500/-	6500-10500/-
6 वें वेतन आयोग (ग्रेड वेतन)	4800	4200 (बाद में 4600/-)

2 (उपरोक्त)

13. अब हम इस पहलू पर आते हैं कि विचाराधीन मामले में पद को सचिवालय या गैर-सचिवालय संगठन का कहा जा सकता है या नहीं। इस पहलू को, एक बार फिर, ***वी. एन. नारायणप्पा और अन्य***[3] के निर्णय में निपटाया गया है, जिसमें स्वामी के 6वें केंद्रीय वेतन आयोग प्रतिवेदन भाग 1 (पृष्ठ 141 से 147) और स्वामी के कार्यालय प्रक्रिया नियमावली 2006 और 2009 का संकलन को ध्यान में रखा गया है। परिभाषा अध्याय में प्रवेश 53 पर, सचिवालय कार्यालयों को उन कार्यालयों के रूप में परिभाषित किया गया है जो सरकार की नीतियों के सूत्रीकरण के लिए और उन नीतियों के कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस परिभाषा पर अवलंबन करते हुए, यह राय दी गई थी कि जिन संगठनों में ***वी. एन. नारायणप्पा और अन्य***[4] में आवेदक कार्य कर रहे थे, वे सचिवालय संगठन नहीं थे, बल्कि गैर-सचिवालय संगठन या संलग्न कार्यालय या उनके अधीन अधीनस्थ कार्यालय थे। अधीनस्थ कार्यालयों का अर्थ क्षेत्रीय स्थापनाओं के रूप में या सरकार की नीतियों के विस्तृत कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के रूप में उनके कार्य को दर्शाना कहा गया है। वे एक संलग्न कार्यालय के निर्देश के तहत या सीधे एक विभाग के तहत कार्य करते हैं। उस संदर्भ में, यह राय दी गई थी कि सचिवालय और गैर-सचिवालय संगठनों के बीच कार्यों, कार्यों और जिम्मेदारियों में एक अंतर मौजूद है। जैसे, यह नोट किया गया था कि यदि संवर्गों के बीच कार्यात्मक असमानताएं हैं, तो वेतन और भत्तों में वित्तीय असमानताएं होना तय है। ***वी. एन. नारायणप्पा और अन्य***[5] के निर्णय के कंडिका38 और 39 को पुनरुत्पादित करना उपयोगी होगा, जो निम्नानुसार हैं:

"38. जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चाओं से स्पष्ट होगा, आवेदकों के बीच जो क्षेत्रीय रेलवे में निजी सचिव ग्रेड-2 हैं, और रेलवे बोर्ड/केंद्रीय सचिवालय सेवाओं/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा या केंद्रीय

---

3 (उपरोक्त)

4 (उपरोक्त)

5 (उपरोक्त)

प्रशासनिक अधिकरण में निजी सचिवों के बीच भर्ती नियमों, पदोन्नति पदानुक्रम आदि में एक महत्वपूर्ण अंतर है। आवेदकों और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में उनके समकक्षों के बीच किसी भी ऐतिहासिक समानता का कोई मामला भी नहीं है। इसलिए आवेदक मूल आवेदन संख्या 164/2009 में एस. आर. धीर और अन्य बनाम भारत संघ में निर्णयों के अनुपात में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा को अनुमति दिए गए वेतनमानों के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में निजी सचिवों को केंद्रीय सचिवालय सेवा के साथ एक ऐतिहासिक समानता की स्थापना के आधार पर लाभ प्रदान किया गया था।

39. इस संदर्भ में, हम उत्तरदाताओं द्वारा किए गए निवेदन पर भी ध्यान देते हैं कि यदि आवेदकों को ऐसा लाभ प्रदान किया जाता है, भले ही उनकी रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के साथ कोई समानता नहीं है और वे इसके हकदार नहीं हैं, तो उत्तरदाताओं के तहत विभिन्न अन्य श्रेणियों/समूहों पर परिणामी निहितार्थ होंगे। रेलवे एक विशाल संगठन है जहां कर्मचारियों के कई संवर्ग/श्रेणियां हैं जिनका क्षेत्रीय रेलवे में निजी सचिवों ग्रेड-2 के समान वेतनमान और समान समानता है। ऐसे समूहों की एक सूची को जवाब बयान में उजागर किया गया है। इसलिए, लाभ का अनुदान जिसके आवेदक अन्यथा हकदार नहीं हैं, रेलवे के अन्य संवर्गों पर भी असर डालेगा जैसा कि निवेदन किया गया है।"

14. हम उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में विश्वास करते हैं कि ***वी. एन. नारायणप्पा और अन्य***[6] में 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कौन सा खंड लागू होगा, इस संबंध में सही दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम पाते हैं कि एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालयों को गैर-सचिवालय संगठनों के रूप में माना जाना है, तो ऐसे

6 (उपरोक्त)

गैर-सचिवालय संगठनों से संबंधित कंडिका 3.1.14 में विशिष्ट सिफारिशें लागू होंगी। कंडिका 3.1.9 में की गई टिप्पणियों को जो सचिवालय कार्यालयों के संबंध में हैं, जो निजी सचिवों/समकक्ष को एक प्रशाखा अधिकारी के साथ समानता देती हैं, उन्हें गैर-सचिवालय संगठनों पर भी *यथावश्यक परिवर्तन* के साथ लागू नहीं कहा जा सकता है। अगर हम अन्यथा राय देते हैं और सभी को समान मानते हैं, तो 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा गैर-सचिवालय संगठनों के लिए अपनी बुद्धिमत्ता में अलग सिफारिशें करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आयोग सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता के निवेदन से अनजान था क्योंकि उससे कंडिका 3.1.2 और 3.1.3 में निपटा गया था, लेकिन उसी पर ध्यान देने के बावजूद सचिवालय और गैर-सचिवालय कार्यालयों के बीच कुछ अंतर करने की मांग की गई थी।

15. वेतन आयोग विसंगतियों को हल करने के उद्देश्य के साथ स्थापित एक विशिष्ट निकाय है। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि विचाराधीन विसंगति को उत्तरदाताओं के समान स्थित उम्मीदवारों के अनुरोध पर वेतन आयोग को भेजा गया था और इस प्रकार, 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग समानता के दावे और उस संबंध में एक सिफारिश करने की आवश्यकता से अवगत था। अपनी बुद्धिमत्ता में बेहतर स्केल देते हुए भी इसने गैर-सचिवालय संगठनों के लिए एक अलग सिफारिश बनाए रखने की मांग की है।

16. हम एक और पहलू पर भी ध्यान दे सकते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा एक निवेदन है कि दोनों संवर्गों के लिए भर्ती प्रक्रिया सामान्य थी और व्यक्तियों को एक से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता था। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वास्तव में, उत्तरदाताओं का निवेदन है कि ऐसे समय रहे हैं जब एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और कभी-कभी परीक्षाएं अलग से आयोजित की जाती थीं। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं की ओर से माननीय अपर महान्यायाभिकर्ता द्वारा यह समझाया गया है कि संवर्ग अलग हैं और

उन्हें नियंत्रित करने वाले नियम भी अलग हैं। रेलवे बोर्ड के तहत आशुलिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1971 द्वारा शासित हैं, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1969 और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 2010 द्वारा शासित हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आशुलिपिक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा नियम, 2013 द्वारा शासित हैं। ये वे पद हैं जिनके साथ उत्तरदाताओं ने समानता की मांग की। दूसरी ओर, क्षेत्रीय रेलवे में कार्य करने वाले उत्तरदाताओं को भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 107 द्वारा शासित किया गया था। यह कहा गया है कि रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे में आशुलिपिकों के पदोन्नति का मार्ग और चैनल पूरी तरह से अलग हैं।

17. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि स्थानांतरण के कुछ मामले थे, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कार्य की आवश्यकता के लिए रेलवे बोर्ड में लाया गया था – ऐसा नहीं था कि उन्हें रेलवे बोर्ड में समाहित किया गया था। ऐसे मामले भी थे जहां रेलवे बोर्ड से क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों में स्थानांतरण हुआ, लेकिन वह ऐसे अधिकारियों के विशिष्ट अनुरोध पर था और मामले-दर-मामले के आधार पर विचार किया गया था और उन्हें तब सूची के अंत में वरिष्ठता लेनी पड़ी थी।

18. कंडिका3.1.3, जिसने सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता से निपटा, क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन के अग्रणी किनारे पर होने के मद्देनजर, क्षेत्रीय कार्यालयों और सचिवालय में नियोजित समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच समानता के लिए एक मामले की वकालत की है। हालांकि, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समानता को सहायक के ग्रेड तक पूर्ण होने की आवश्यकता होगी। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि उससे परे *"पूरी समानता देना संभव या यहां तक कि न्यायोचित भी नहीं हो सकता है क्योंकि कार्यात्मक विचारों और सापेक्षताओं को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम और करियर प्रगति को*

पूरे बोर्ड में अलग होना होगा।" यदि इस सिद्धांत का पालन किया जाता है, तो लाभ उत्तरदाताओं को नहीं मिल सकता है और हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सहायक के स्तर तक समानता दिए जाने के परिणामस्वरूप (जो उन्हें ₹4200 (बाद में ₹4600) के ग्रेड में रखेगा), उत्तरदाताओं को, एक पद उच्च होने के कारण, स्वचालित रूप से एक उच्च ग्रेड मिलना होगा।

19. हम वेतन आयोग के उपर्युक्त कंडिकाओं की व्याख्या में जिस राय को अपनाना चाहते हैं, उसे ***भारत संघ बनाम तारित रंजन दास***[7] में टिप्पणियों से पुष्ट किया जाता है, जहां यह राय दी गई थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को केवल पदनाम के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में 5 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से निपटते हुए, यह माना गया था कि उस आधार पर किसी भी समतुल्यता का कोई प्रश्न नहीं था। उक्त मामला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आशुलिपिकों से संबंधित था। यह टिप्पणी करते हुए कि एक सामान्य बयान के रूप में यह कहना सही था कि एक आशुलिपिक के कार्य की मूल प्रकृति बहुत हद तक समान रही, चाहे वे सचिवालय में एक अधिकारी के लिए कार्य कर रहे थे या एक अधीनस्थ कार्यालय में एक अधिकारी के लिए; यह माना गया था कि न्यायालयों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि आयोग ने स्वयं सभी पहलुओं पर विचार किया था और उचित विचार के बाद राय दी थी कि पूर्ण समानता नहीं दी जानी चाहिए।

20. अंत में हम दोहराना चाहेंगे कि सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच असमानता का पहलू सिफारिशें करते समय स्वयं आयोग द्वारा ध्यान में लिया गया एक मामला था। फिर भी कुछ हद तक, सचिवालय संगठनों और गैर-सचिवालय संगठनों के संबंध में एक अलग सिफारिश की गई थी। एक बार जब ये सिफारिशें अलग से की जाती हैं, तो पूर्ण समानता का निर्देश देना गैर-सचिवालय संगठनों के संबंध में अलग सिफारिशों को व्यर्थ

7 (2003) 11 एससीसी 658

कर देना होगा। यदि कोई कह सकता है, तो इन अलग सिफारिशों को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि सभी को हर पहलू पर समानता पर माना जाना होता।

21. उपर्युक्त कारणों के मद्देनजर, हम आक्षेपित निर्णय को असंधारणीय पाते हैं, जो बदले में विभिन्न अधिकरणों और न्यायालयों द्वारा पारित अन्य आदेशों पर अवलंबन करता है, और तदनुसार अपास्त किया जाता है।

22. अपीलें तदनुसार अनुज्ञात हैं।

23. हमें उम्मीद है कि यह इस विवाद को समाप्त कर देगा जिसे इस न्यायालय की अंतिम युक्तियुक्त राय प्राप्त किए बिना विभिन्न मंचों के सामने उठाया गया है।

अपीलें अनुज्ञात।

अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।